साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 05-11 जून 2023 वर्ष-9, अंक-8

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

पंजाब नौंवे और हरियाणा 16वें स्थान पर

एसओई इन फिगर्स 2023 | कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल

भोपाल। जागत गांव हमार

स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स 2023 रिपोर्ट में मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में पहली रैंकिंग हासिल की है। देश के सभी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश ने कृषि के शुद्ध मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भी राज्य का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश ने कुल 10 में से 7.715 अंक हासिल कर शेष राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर हैं, जिन्हें क्रमशः 5.950, 5.375, 5.361 अंक हासिल हुए हैं।

निचले पायदान पर रहने वाले राज्य

दिल्ली, गोवा, मेघालय और केरल हैं। दिल्ली को 0.106, गोवा को 1.786, मेघालय को 2.933 और केरल को 3.470 अंक ही हासिल हुए हैं। निचले पायदान पर मौजूद 10 राज्यों में से 6 राज्य हिमालयी हैं। हालांकि त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे हिमालय राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और ये राज्य छठे, सातवें और आठवें पायदान पर मौजूद हैं।

सबसे खराब प्रदर्शनः दिल्ली, गोवा और केरल

कृषि क्षेत्र की यह रैंकिंग आठ संकेतकों पर आधारित हैं। इन संकेतकों में कृषि, वानिकी और मछली उत्पादन को सर्वाधिक 3 भारांक दिए गए हैं। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन, बागवानी उत्पादन, दूध उत्पादन, पोल्ट्री उत्पादन, मांस उत्पादन, बीमित फसल क्षेत्र और डिग्रेडेड भूमि को भी संकेतकों में शामिल किया गया है। इन सभी संकेतकों के 1-1 भारांक हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। वहीं इस क्षेत्र में दिल्ली, गोवा और केरल का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा। खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात सबसे आगे रहे जबकि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का प्रदर्शन निचले दर्जे का रहा। बागवानी उत्पादन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और त्रिपुरा ने बाजी मारी, वहीं तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा का प्रदर्शन निम्नतम रहा।

बीमित फसल क्षेत्र में भी मप्र रहा अव्वल

इसी तरह दूध उत्पादन में सिक्किम, त्रिपुरा और राजस्थान अव्वल रहे और केरल, मिजोरम और तेलंगाना सबसे निचले पायदान पर रहे। पोल्ट्री उत्पादन के पैमाने पर ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहे जबकि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। कृषि क्षेत्र के एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक बीमित फसल क्षेत्र में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान अव्वल रहे। यानी इन तीन राज्यों का सर्वाधिक फसल क्षेत्र बीमा के दायरे में है। गोवा, सिक्किम और मेघालय इस संकेतक पर सबसे पीछे हैं। भूमि का डिग्रेडेशन मिट्टी की उर्वरता शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसलिए इस संकेतक को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस पर सबसे अच्छा प्रदर्शन अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश का है जबकि झारखंड, राजस्थान और दिल्ली सबसे निचले पायदान पर हैं। मप्र में इस बार रबी सीजन में 15 लाख से ज्यादा किसानों ने गेहूं की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार की 70 लाख टन गेहूं खरीदे जाने की तैयारी थी, जो 71 लाख टन हुआ। देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को अनाज वितरण के लिए गेहूं का स्टाक 30 लाख मिलियन टन रखना होता है, जिसे सार्वजनिक उपभोक्ता भंडार के जरिए गरीबों में बांटा जाता है।

भोपाल का हाल बेहालः सुविधाओं के अभाव में खाली पड़ीं 14 गौशालाएं

शर्मनाक! सड़क पर दस हजार गाय

भोपाल। जागत गांव हमार

भोपाल में सड़कों पर बेसहारा घूम रहीं गाय हादसे का कारण बनती हैं। इनमें लोगों के घायल होने के साथ ही गाय को भी चोट आती है। जबकि गायों को सुरक्षित करने जिले में गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा पंचायतों में 14 गौशालाएं बनवा दी गई हैं। हालांकि इनमें अब तक गाय नहीं रखी जा सकी हैं। दरअसल, गौशालाओं में बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं नहीं होने से गौवंश की शिफ्टिंग नहीं हो सकी है। इस वजह से सड़कों पर 10 हजार से अधिक गाय घूम रही हैं। वहीं हर साल 100 हादसे होते हैं। जिले की ग्राम पंचायतों में गौशालाएं बनवाने का काम मनरेगा के पास है। वर्ष 2020-21 में 30 गौशालाएं स्वीकृत की गई थीं जिनका निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। इनमें से 16 गौशालाएं बनकर तैयार हो गई हैं और 14 अब भी निर्माणाधीन हैं। पूर्ण हो चुकी दो गौशालाएं ग्राम पंचायत मनीखेड़ी और ललोई में शुरू हो चुकी हैं। जिनमें गौवंश रखे जा चुके हैं, लेकिन बाकी 14 बन तो गई हैं, लेकिन इनमें अब तक गायों को रखने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

सवा तीन करोड़ से बनाईं थीं 12 गौशाला

गायों को छह लाख दान में मिले पर माननीयों ने नहीं दी फूटी कौड़ी पेज-02 पर पढ़ें

वर्ष 2019- 20 में मनरेगा ने 12 गौशालाओं का निर्माण किया था। जिनकी लागत लगभग 3.32 करोड़ रुपए आई थी। इन सभी गौशालाओं का संचालन शुरू हो चुका है और इनमें 1100 से अधिक गौवंश रखे गए हैं। यदि जिम्मेदार जिला पंचायत और पुशपालन विभाग के अधिकारी पूर्ण हो चुकी गौशालाओं पर ध्यान दें तो सड़कों पर घूमने वाले गौवंश की संख्या में कमी आएगी।

- हमारा काम गौशाला में गायों के लिए चारे, भूसे की व्यवस्था कराना है। साथ ही उनका समय पर बेहतर उपचार करना है। यदि गौशालाओं में गाय नहीं हैं तो जिला पंचायत के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।
  डॉ. अजय रामटेके, उपसंचालक पुश चिकित्सा सेवाएं
- जिले की पंचायतों में गौशालाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अधिकांश गौशालाएं बनकर तैयार हैं। जल्द ही इनमें गायों को रखवाएंगे।
  रितुराज सिंह, सीईओ, जिला पंचायत, भोपाल

यह गौशालाएं हो चुकीं तैयार

गौशाला	लागत
समरधा	30 लाख
करटइ	30 लाख
कलाखेड़ी	30 लाख
बरखेड़ा	38 लाख
बिलखिरिया	38 लाख
आदमपुर	38 लाख
कालापानी	38 लाख
सिकंदराबाद	38 लाख
अगरिया	38 लाख
अमझरा	38 लाख
बरोड़ी	30 लाख
दामखेड़ा	30 लाख
धूतखेड़ी	30 लाख
बर्री बगराज	38 लाख

नशामुक्त पंचायत को दो लाख का पुरस्कार देगी मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश की नशा मुक्त ग्राम पंचायत को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। सम्मान स्वरूप पंचायत को दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी। वर्ष 2018 में नशामुक्त ग्राम पंचायत को एक लाख रुपए पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया था और प्रत्येक जिले में किसी एक ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई थी। अब प्रदेश की नशामुक्त ग्राम पंचायतों को एक लाख रुपये के स्थान पर दो लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसी ग्राम पंचायत जहां निवासरत युवा, वृद्ध एवं महिलाएं नशामुक्त जीवन यापन कर रहे हैं, सम्मान की पात्र होगी। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश की नशामुक्त ग्राम पंचायतों को दो लाख रुपए की राशि एवं प्रशंसा पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। नशामुक्त ग्राम पंचायतों का तय मापदंड के अनुसार चयन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष ऐसी चयनित ग्राम पंचायतों को गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

- पंचायतों को पहले दिया जाता था एक लाख का पुरस्कार
- गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कृत की जाएंगी पंचायत

2023-24: 27 लाख मीट्रिक टन गेहूं ज्यादा खरीदा, नौ हजार करोड़ रुपए का ज्यादा लेना पड़ा कर्ज

सरकार ने अब तक की 71 लाख मीट्रिक टन खरीदी

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं की खरीदी की, जिस पर उसे 9 हजार करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। इस राशि पर हर रोज 12 करोड़ रुपए ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है। साल 2023-24 में 71 लाख टन गेहूं की खरीदी हुई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 43.3 लाख टन गेहूं की खरीदी हुई थी। हालांकि इस साल ज्यादा गेहूं की खरीदी केंद्र सरकार के प्रोत्साहन पर की गई है। इस खरीदी का केंद्र सरकार जैसे-जैसे उठाव होता जाएगा, उसमें 90 रुपए प्रति टन के हिसाब से 9 महीने का पूरा खर्च ब्याज एवं कर्ज ली गई राशि की भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

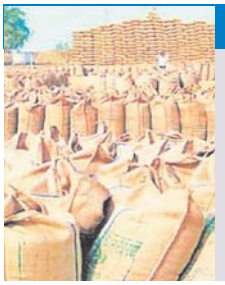

इस साल गेहूं खरीदी के लिए 10468 करोड़ रुपए कर्ज लेना था, जिसके लिए 29336 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी गई थी। इस तरह इस साल का गेहूं खरीदी का खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम का खर्चा 39804 करोड़ रुपए था। साथ ही गेहूं खरीदी के लिए मार्कफेड ने 12832 करोड़ रुपए का खर्च लिया हुआ है। इस तरह गेहूं खरीदी का कर्ज 52636 करोड़ रुपए हो गया है।

गेहूं खरीदी का कर्ज 52636 करोड़ रुपए

500 टन गेहूं भीग | मप्र में इस साल गेहूं की खरीदी के केंद्र गोडाउन में बनाए जाने से परिवहन के 250 करोड़ रुपए की बचत हुई। प्रदेश में रबी सीजन में 71 लाख टन गेहूं खरीदी हुई। गोडाउन में गेहूं की हुई कुल खरीदी का 80 फीसदी भंडारण हुआ, जबकि 20 प्रतिशत खरीदी खरीदी केंद्रों पर हुई, जिससे असमय बारिश की वजह से 500 टन गेहूं भीग गया।

15 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन | मप्र में इस बार रबी सीजन में 15 लाख से ज्यादा किसानों ने गेहूं की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार की 70 लाख टन गेहूं खरीदे जाने की तैयारी थी, जो 71 लाख टन हुआ। देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को अनाज वितरण के लिए गेहूं का स्टाक 30 लाख मिलियन टन रखना होता है।

इस बार गेहूं खरीदी के बाद बारदाना (बोरे) केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराए, जिससे हर साल होने वाली बारदाना खरीदी के 275 करोड़ रुपए की बचत रही। इस तरह 525 करोड़ रुपए की बचत हुई।
तरुण पिथोड़े, एमडी, मप्र वेयर हाउस कार्पोरेशन

मोटे अनाज, प्राकृतिक और जैविक खेती के जरिए बढ़ेगी आय

ड्रोन और आधुनिक तकनीक से खेती कर किसान बनेंगे अत्मनिर्भर

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए जागरूक किया जाएगा। जिससे किसान कम समय में ड्रोन सहित अन्य आधुनिक तकनीक अपनाने हुए उन्नत खेती तो करेंगे ही साथ में वह समृद्ध भी बनेंगे। वहीं मिलेट यानि मोटे अनाज और प्राकृतिक, जैविक खेती के जरिए किसान अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भोपाल सहित अन्य जिलों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं धान उत्पादक जिलों में पूसा धान और सोयाबीन, उड़द के नए बीज का व्यापक रूप में बुआई में उपयोग करने के साथ ही कृषि में नैनो यूरिया का प्रयोग बढ़ाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त वीरा राणा ने जिले के सभी कलेक्टरों, कृषि विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

बीजों को प्रोत्साहन करने अभियान

किसानों को उन्नत किस्म का बीज मिल सके इसके लिए बीजों को प्रोत्साहित करने अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में बीज का पर्याप्त भंडारण है और ऐसे किसान जो बीज उत्पादक हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा।धान की नरवाई के निराकरण के लिए आई मशीनों को कस्टम हायर सेंटर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।वहीं मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाओं को ब्लाकस्तर पर और सशक्त एव उपचार विधि को परीक्षण से जोड़ने के लिए स्थानीय युवाओं को संचालन सौंपा जाएगा।

ऋण वितरण में अर्जित करें उपलब्धि

मुख्यमंत्री किसान ब्याज माफी योजना में अब तक जमा किए गए आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए है। इस दौरान किसानों को कृषि फसल ऋण वितरण में शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के लिए कहा गया है।सहकारी समितियों का अभियान चलाकर विस्तार किया जाए और समितियों को अन्य लाभप्रद गतिविधियों से जोड़ा जाए। नई सहकारी समितियों के गठन पर भी जोर दिया जाए।

फसलों पर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट

उद्यानिकी फसलों पर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे।फुड प्रोसेसिंग पार्क पर चल रहे कार्य को और बेहतर बनाए जाएंगे। नरेगा के मद से नर्सरियों की फेंसिंग और मरम्मत कार्य के साथ ही खेत-तालाब आदि का भी निर्माण करवाया जाएगा। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा समय देकर रकबा और उत्पादन ब ?ाकर बाजार उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जाएंगे।

गौशालाओं में बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गौशालाओं के संचालन और निर्माण का कार्य तेजी से किया जाएगा। जिन गौशालाओं में बिजली और पानी की व्यवस्था की जाएगी। मत्स्य संपदा योजना के साथ पशुपालकों तथा मत्स्य उत्पादकों को शत प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। तालाबों को मत्स्य पालन के लिए दिए जाने के कार्य किए जाएंगे। कृषि विकास प्लान को एक जून से लागू किया जाएगा।

गौपालन बोर्ड के अध्यक्ष ने गौग्रास के लिए 10 रुपए दान का किया था आह्वान

गायों को छह लाख दान में मिले पर माननीयों ने नहीं दी फूटी कौड़ी

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में गायों को लेकर हमेशा राजनीति होती है, लेकिन जब उनके लिए दान देने की बात आती है तो जनप्रतिनिधि मुट्ठी बांध लेते हैं। गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड ने सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों समेत आम लोगों से गौग्रास के प्रतिदिन 10 रुपए दान करने का आग्रह किया था। एक वर्ष में छह लाख रुपए दान में मिले, लेकिन किसी विधायक या सांसद ने एक रुपए भी दान नहीं किया। गौरतलब है कि गौशालाओं को सरकार की तरफ से प्रतिदिन प्रति गाय सिर्फ 20 रुपए भोजन और अन्य खर्च के लिए दिया जाता है, जो बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में यह राशि 30 रुपए है। प्रदेश में एक हजार 762 गौशालाएं हैं। गौवंश की कुल संख्या दो लाख 87 हजार है। गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी ने पिछले वर्ष चैत्र प्रतिपदा से गौग्रास के लिए हर व्यक्ति से प्रतिदिन 10 रुपए दान करने का आह्वान किया था। इसके पीछे उनका तर्क यह था कि पहले लोग भोजन के पूर्व गाय के लिए एक रोटी निकालते थे।

» गौशालाओं को सरकार की तरफ से हर दिन प्रति गाय 20 रुपए

» भोजन और अन्य खर्च के लिए दिया जाता है, जो बहुत कम

अखिलेश्वरानंद का पत्र भी बेअसर

अब शहरों में रोटी खिलाने के लिए गाय नहीं मिल पातीं, इस कारण प्रति रोटी 10 रुपए के मान से दान करें तो एक वर्ष में तीन हजार 650 रुपए एकत्र हो जाएंगे। अखिलेश्वरानंद गिरी ने सभी विधायकों और सांसदों को प्रतिदिन 10 रुपए दान करने या फिर वर्ष में एक दिन का वेतन दान करने के लिए पत्र भी लिखा था। इसके बाद भी किसी ने गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के खाते में एक रुपए भी दान नहीं किया है।

वास्तविकता ने दिखाई राजनीतिक दलों के नेताओं की संवेदनशीलता

हालांकि, आमजन की बात करें तो 400 से अधिक लोगों ने छह लाख रुपए गौशालाओं के लिए दान किया है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। भाजपा सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाने जा रही है। कांग्रेस भी अपने वचन पत्र में इसे शामिल करने की तैयारी में है। गौशालाओं की दुर्दशा को लेकर दोनों पार्टियां एक-दूसरे को कोसती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता में गाय के प्रति दोनों दलों के नेता कितने संवेदनशील हैं यह सामने आ गया है।

कृषि विकास विभाग की उपसंचालक ने किसानों को दी सलाह

100 में से 75 दाने हों अंकुरित तब ही समझें बीज बोवनी योग्य

भोपाल। जागत गांव हमार

खरीफ के मौसम में सोयाबीन सहित अन्य फसलों को बोने के लिए पहले बीज को अंकुरण करके देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सोयाबीन हो या फिर अन्य बीज उसके 100 दानों को अंकुरित किया जाना चाहिए। यदि 100 में से 75 से अधिक दाने अंकुरित होते हैं तो वही बीज बोने योग्य होता है। इससे किसान को बेहतर उपज मिलती है। यह सलाह किसानों को कृषि विकास विभाग की उपसंचालक सुमन प्रसाद ने दी है। दरअसल, अब किसान ने खरीद के मौसम की फसलों को बोने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है इसी वजह से कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह और मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल बोवनी से पहले किसानों को बीज का अंकुरण कर परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसल के लिए उर्वरक व्यवस्था समिति या निजी व्यापारी से अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर भंडारित करें। जिससे बोवनी के समय पर किसानों को कोई असुविधा न हो।

प्राकृतिक खेती पर जोर

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। किसान प्रायोगिक तौर पर प्राकृतिक खेती के घटक को सोयाबीन फसल पर प्रयोग कर परिणाम ले सकते हैं। आगामी फसलों के अधिक रकबे पर प्राकृतिक खेती करें। बीज उर्वरक एवं कीटनाशक क्रय से संबंधित संस्थाओं से पक्के बिल लेना जरूरी है। फसल विविधीकरण अपनाकर एक से अधिक फसल लें ताकि अल्प, अधिक वर्षा होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। साथ ही बीज का चयन करते हुए नवीन किस्म (10 वर्ष के अंदर) का चयन करें।

डिजिटल होंगे किसान क्रेडिट कार्ड

राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है। पद्धति के कंप्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी। इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन आनलाइन एप से किए जा सकेंगे। साथ ही कृषि भूमि का सत्यापन भी आनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार

नई दिल्ली/भोपाल। भारत सरकार कृषि मंत्रालय के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कृषक समूहों एंव किसानों को परंपरागत व देसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। 2022-23 के पादप जीनोम पुरस्कार उन किसानों एंव कृषक समूहों के लिए अच्छा मौका है, जो किसान किसी भी परंपरागत देसी प्रजातियों का संरक्षण एंव चयन करके विकास का कार्य कर रहे हैं, वे किसान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के तहत अपना पंजीयन करवा कर पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।

पादप जीनोम पुरस्कार के लिए आवेदन कैसे करें- पादप जीनोम पुरस्कार किसान एवं कृषक समूहों को आवेदन करने का तरीका काफी सरल रखा गया। किसान पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के नई दिल्ली कार्यालय या प्राधिकरण कार्यालय की शाखा गुवाहाटी, पालमपुर, पुणे और शिवमोग्गा से व्यक्तिगत रूप से या डाक पोस्ट द्वारा भी कर सकते हैं। आवेदन हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में जमा किया जा सकता हैं और आवेदन प्रक्रिया नि:शुल्क रखी गई हैं।

क्या हैं आवेदन की आखिरी तारीख व पुरस्कार राशि

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के तहत एक वर्ष में पांच किसान समूहों को पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रत्येक समुदाय को दस लाख रुपए तक का पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में कृषक पुरस्कार के तहत एक वर्ष में दस किसानों के लिए ये पुरस्कार है। इसमें प्रत्येक किसान को डेढ़ लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

मान्यता पुरस्कार| पादप जीनोम संरक्षक मान्यता पुरस्कार के तहत एक वर्ष में बीस किसानों को मान्यता पुरस्कार मिलेगा। इसमें प्रत्येक किसान को एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2023 रखी गई है।

खंडवा की महिलाओं ने उगाया 800 रुपए किलो का फूल, विदेशों में भी बढ़ी डिमांड

कुसुम की खेती चमकी किस्मत

-दस हजार रुपए की लागत और मुनाफा 60 हजार तक हो रहा

खंडवा। जागत गांव हमार

खंडवा जिले की कई महिलाएं परंपरागत खेती से हटकर कुसुम की खेती कर रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार का ग्रामीण आजीविका मिशन गांवों में वैज्ञानिक पद्धति से 'कुसुम' की खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं का समूह बनाया है। इस समूह से ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं, जो पहले गेहूं, धान, सोयाबीन की खेती किया करती थीं। कड़ी मेहनत के बाद भी लागत निकाल पाना मुश्किल हो जाता था। ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत पंधाना ब्लॉक प्रबंधक मीनूसिंह चौहान ने पंधाना के कई गांवों की महिलाओं को कुसुम की खेती के प्रति जागरूक किया। साथ ही उन्हें इसकी खेती से जुड़ी जानकारी, बीज और पैदावार के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया है।

खंडवा में स्व-सहायता समूह की 120 महिलाओं ने पहली बार 125 एकड़ में कुसुम फूल की खेती शुरू की है। रंग-बिरंगे फूलों की इस खेती में अच्छी पैदावार से महिलाएं उत्साहित हैं। पहली बार में ही 22 लाख रुपए की कमाई हुई है। इसका इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। इसके फूलों की डिमांड राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों और विदेशों तक है। पंधाना जनपद क्षेत्र के कुमठा गांव में 12 महिलाएं एक साथ कुसुम की खेती कर रही हैं। गुढ़ी कलस्टर के लुनहार गांव में भी खेती शुरू की गई है।

60 हजार रुपए एकड़ मुनाफा

लुनहार की तुलना में कुमठा में ज्यादा महिलाएं खेती कर रही हैं। कुसुम का जैसा नाम है, वैसा ही इसका दाम भी है। उत्पादन प्रति एकड़ सिर्फ 80 किलो होता है, लेकिन इसके फूलों की कीमत 80 हजार रुपए प्रति क्विंटल होने यह करीब 60 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुनाफा होता है। खास बात यह कि इसकी लागत सिर्फ मात्र 10 हजार रुपए प्रति एकड़ आती है।

लगभग 15 जार खर्च

लगभग 15 हजार खर्च हुए। बीते अक्टूबर में बोवनी के चार माह बाद फसल तैयार हो गई। उत्पादन करीब डेढ़ क्विंटल हुआ है। बेहतर उत्पादन हुआ तो कुसुम के फूल और बीज दोनों मिलाकर 1.65 लाख की फसल बिकी। फूल निकलने के बाद बीज से तेल व खली का भी अच्छा भाव मिल जाता है। जैविक खाद से जमीन तैयार करने के बाद सिर्फ बीज लाकर बोवनी करनी होती है। इसके बाद हल्की निंदाई-गुड़ाई करनी पड़ती है। बाकी रासायनिक खाद और दवाओं का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है। इसकी वजह से लागत खर्च की बचत हो जाती है। पहली बार कुसुम की खेती करने वाली 10 महिलाएं लखपति बन गई हैं।

फूल और बीज से मुनाफे का गणित

एक एकड़ में लागत अधिकतम 10 हजार रुपए। पैदावार प्रति एकड़ 80 किलो सूखा फूल। फूल की कीमत 60 हजार रुपए क्विंटल मिलेगी। इस हिसाब से प्रति एकड़ 50 हजार रुपए फूल से मुनाफा होता है। बाकी प्रति एकड़ 5 क्विंटल बीज निकलता है, जो 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिकता है। इस लिहाज से 15 हजार रुपए का बीज हो जाता है। इस तरह एक एकड़ में कुल 65 हजार रुपए तक का फायदा हो जाता है। फसल बेचने के लिए मार्केट भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आसानी से सभी महिलाएं एक जगह फूलों का इकट्ठा कर लेती हैं और बाहर के व्यापारी यहां आकर इसे खरीद ले जाते हैं।

एक हजार एकड़ में खेती

मीनू सिंह चौहान बताती हैं कि महिला किसानों को शुरुआती साल में आयुर्वेद संस्थान से बीज उपलब्ध कराया था। वर्तमान में हमारे पास बीज की उपलब्धता काफी है, इसलिए इस साल अक्टूबर में प्लानिंग है कि 125 एकड़ की बजाय एक हजार एकड़ में कुसुम की खेती की जाएगी। इसके लिए किसानों ने भी सहमति जताई है। कुसुम के फूलों को आयुर्वेदिक कंपनियों को बेचा जा रहा है। अनुमान है कि गरीब किसानों के बीच इस आयुर्वेदिक खेती का दायरा बढ़ेगा। आगे प्लान यह है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर किसानों को बीज उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं फल-फूल और पत्ती से हमारे प्रोडक्ट तैयार कर खुद बाजार में उतारेंगे।

वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन

महिला किसान कला जमरा ने बताया कि शुरुआत में हिचकिचाहट हुई, लेकिन बीज की उपलब्धता और वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिला तो खेती शुरू की। रबी सीजन में पानी की कमी से गेहूं और चने की पैदावार इतनी नहीं होती कि परिवार का भरण-पोषण किया जा सके। जब कुसुम की पहली खेती में पारंपरिक खेती से कई गुना ज्यादा आमदनी हुई।

कुसुम के किस्मों की खासियत

- **के- 65:** यह कुसुम की सबसे उन्नत किस्म है। इसे तैयार होने में 180 से 190 दिन का समय लग जाता है।7 इसमें तेल की मात्रा 30-35 फीसदी होती है। इसकी औसतन उपज प्रति हेक्टेयर 14 से 15 क्विंटल होती है।
- **मालवीय कुसुम 305:** कुसुम की यह किस्म 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके बीज से 36 फीसदी तेल की मात्रा मिल जाती है।
- **ए- 300:** यह किस्म 160 से 170 दिन में पक जाती है। प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन 8 से 9 क्विंटल ही होता है। इसमें निकलने वाला फूल पीले रंग का होता है। बीज सफेद और के-65 की तुलना में छोटे होते हैं। इसके बीज से 31.9 प्रतिशत तेल की मात्रा मिलती है।
- **कुसुम-1:** कुसुम की यह प्रजाति-300 की तरह ही 160 दिनों में पककर तैयार होती है। प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन 8 से 10 क्विंटल होता है। इससे 30.8 प्रतिशत तेल की मात्रा निकलती है।
- **अक्षागिरी 59-2:** यह किस्म प्रति हेक्टेयर4 से 5 क्विंटल की पैदावार देती है। इसकी फसल 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें निकलने वाले फूल पीले और बीज सफेद रंग का होता है।

कुसुम के तेल का उपयोग

- सीने के दर्द होने पर कुसुम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग सिर्फ डॉक्टरों की सलाह पर ही किया जाना चाहिए।
- रोजाना डेढ़ चम्मच कुसुम के तेल का सेवन करने से लाभ मिलता है। इसमें ओलिक एसिड होता है, जिसके सेवन से हृदय रोग से बचने में मदद मिलती है।
- एक साल तक कुसुम का तेल का सेवन करने से बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस के लक्षण को बढ़ने से रोकता है।
- कुसुम के फूल के सैफलोवर येलो को नसों के माध्यम से रोगी को देने से मधुमेह के कारण होने वाली किडनी की समस्या को कम होती है।
- कुसुम के फूलों से लेकर इसके पौधे का हर हिस्सा उपयोगी है। इससे तेल और शरबत के अलावा साबुन, पेंट, वार्निश आदि बनाए जाते हैं।
- बाजार में कुसुम के फूल से बना एसेंशियल ऑइल और शहद की भी काफी डिमांड होती है।

कृषि अधिकारियों को दिया गया पौध संरक्षण प्रशिक्षण

बैतूल। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल द्वारा जिले में मैदानी स्तर पर कार्यरत कृषि अधिकारियों को खरीफ फसलों खासकर सोयाबीन एवं मक्का में पौध संरक्षण प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 2 से 3 जून 2023 के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 70 कृषि अधिकारियों को प्रमुख खरीफ फसलों के कीट व्याधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में केन्द्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. व्ही.के. वर्मा ने इस प्रशिक्षण की महत्ता एवं प्रशिक्षण की विधियों, कृषकों तक अपनी बात पहुंचाने के तरीकों पर कृषि अधिकारियों से चर्चा की। केन्द्र के पौध संरक्षण वैज्ञानिक आर.डी. बारपेटे द्वारा सोयाबीन, मक्का एवं धान के प्रमुख कीट रोग, उनके जीवन चक्र, पहचान एवं प्रबंधन के एकीकृत उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। शस्य वैज्ञानिक डॉ. मेघा दुबे द्वारा खरीफ फसलों में पोषक तत्व एवं खरपतवार प्रबंधन के एकीकृत उपाय बतायें जिनसे लागत कम हो एवं शुद्ध लाभ बढ़े। डॉ. संजय जैन, पौध प्रजनक द्वारा खरीफ की प्रमुख फसलों की विपुल उत्पादन देने वाली नवीनतम प्रजातियों के बारे में कृषि अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिले के उप संचालक कृषि आर.जी. रजक के विशेष अनुरोध पर सभी विभागीय अधिकारियों को ये प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्र पर कार्यरत खाद्य वैज्ञानिक डॉ. एम.पी. इंगले एवं सौरभ मकवाना के सक्रिय सहयोग से कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

पर्यावरण असंतुलन बन रहा खेती के लिए चुनौती

विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड)

एक समय था जब गांवों को पर्यावरण का सबसे बड़ा हितैषी एवं मित्र माना जाता था। गांवों में हरे भरे पेड़-पौधे, लहलहाती फसलें, पशु पक्षियों का कलरव एवं चिड़ियों की चहचहाहट बरबस ही लोगों का ध्यान आकृष्ट करती थी। परंतु आज पर्यावरण के सबसे बड़े मित्र समझे जाने वाले गांव ही उसके दुश्मन बन गए हैं।

हमें प्रकृति से कम से कम लेकर उसे ज्यादा से ज्यादा लौटना चाहिए तभी हमारी पृथ्वी और पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा। लेकिन उपभोग वाली संस्कृति ने प्रकृति से ज्यादा से ज्यादा लेकर बहुत कम लौटाया है। यही कारण है कि आज पर्यावरण और प्रकृति दोनों ही खतरे में दिखाई पड़ती हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी आज भी अधिकांश जनसंख्या खेती-किसानी पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या की चुनौती को देखते हुए कृषि में पर्यावरण की उपयोगिता का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। खेती-बाड़ी में हमारे किसानों द्वारा अधिकाधिक उपज व निरोगी फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए असंतुलित मात्रा में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बिना सोचे समझे प्रयोग किया जा रहा है। इसके कारण खेतों की मिट्टी से लेकर वायु, पानी, फल, सब्जी, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, दूध, मांस आदि के दूषित होने के साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। गांवों के तालाबों, नदियों, नहरों एवं कीटनाशकों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। जिसके कारण गांव का पर्यावरण ही प्रदूषित नहीं हो रहा वरन खेती में पैदा की जा रही स्वास्थ्यवर्धक कृषि उत्पादों के प्रयोग से ही स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक खतरा पैदा हो गया है।

खेती में कीटनाशकों का प्रयोग रोगों से बचाव के लिए किया जाता है। जबकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक उपज प्राप्त करने के लिए होता है। कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों व रासायनिक उर्वरकों की खपत पर दृष्टि डाली जाए तो पिछले दो दशक में इनकी खपत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। चिंताजनक पहलू यह है कि किसान अपने स्तर से भी कई दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि घातक हैं। आज सभी का एकमात्र उद्देश्य उपज बढ़ाना व अधिक आमदनी प्राप्त करना है। यदि इससे लोगों का स्वास्थ्य व पर्यावरण असंतुलित होता है तो उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आज कृषि वैज्ञानिकों द्वारा संतुलित उर्वरकों के प्रयोग तथा एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है।

कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से जहां पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वहीं खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसान के मित्र कीट भी मारे जा रहे हैं। जिसके कारण शत्रु कीटों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जोकि खेती-बाड़ी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। यदि खेतों व फसलों में मित्र कीटों की पर्याप्त संख्या रहेगी तो शत्रु कीटों को पनपने का मौका नहीं मिल पाएगा जिससे फसलों पर कीटों का प्रकोप बहुत कम होगा।

कीटनाशकों के प्रयोग से जहां अनजाने में ही किसानों के मित्र कीट मारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फसलों व किसानों को विभिन्न रूपों में सहायता करने वाले अनेकों पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो गई हैं। पक्षियों की यह प्रजातियां पौधों

में परागण से लेकर शत्रु कीटों को खाकर पर्यावरण शुद्ध रखने का काम करते हैं। इन पक्षियों में प्रमुख रूप से गौरैया, गिद्ध, पहाड़ी बटेर, तोता, बया, कठफोड़वा, सफेद कबूतर, हरियल पक्षी, नीलकंठ, सारस, जलकुकरी आदि या तो दिखाई नहीं देते हैं या फिर नाम मात्र को ही दिखाई पड़ते हैं।

खरपतवारों के बचाव के लिए निराई-गुड़ाई एवं आच्छादन जैसी जैविक क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए जिससे खरपतवारनाशकों का प्रयोग रोका जा सके। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के साथ ही जैव उर्वरक, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाए। किसान जैविक एवं प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए आगे आयें जिससे पर्यावरण प्रदूषण को और अधिक खराब होने से रोका जा सके।

शहरों के साथ ही गांवों में भी पॉलीथिन का प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है। इसके पीछे प्रमुख कारण पॉलीथिन की थैली का बोलबाला है इसे यूज एंड थ्रो की संस्कृति ने बढ़ावा दिया है। पॉलीथिन पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी शत्रु है। पॉलिथीन एक ऐसा तत्व है जिसे जमीन में दबा देने पर भी नष्ट होने में लगभग 200 वर्ष का समय लग जाता है। यदि जलाया जाए तो इससे अनेकों विषैली गैसें निकलती हैं। जो मानव के साथ-साथ पेड़-पौधों एवं पशु-पक्षियों पर भी काफी हानिकारक प्रभाव डालती है। जमीन में प्लास्टिक अथवा पॉलीथिन दबा देने पर उसके आसपास का सतही जल भी प्रदूषित हो जाता है। क्योंकि इससे जमीन के भीतर जल में विषैले तत्व पहुंच जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जिस अनुपात में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। उस अनुपात में नए वृक्षों को नहीं लगाया जा रहा है। किसी जमाने में जहां जंगल ही जंगल थे आज वहां वृक्षों का नामोनिशान तक नहीं हैं। इसके चलते औसत वर्षा का अनुपात गिरने के कारण सूखा की स्थिति बनने से वायुमंडलीय तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। बरसात, सर्दी, गर्मी की ऋतुओं का प्राकृतिक पर्यावरणीय संतुलन गड़बड़ा गया है, जिससे फसलों में रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ने के साथ ही उत्पादन भी गिर रहा है।

पर्यावरण संतुलन के बिगड़ने के कारण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी के कारण हिमखंडों के पिघलने का खतरा मंडराने लगा है। जिसके कारण नदियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। सिंचाई के अभाव के कारण फसलें सूख जाएंगी और बाढ़ जैसी विभीषिका भी पैदा होगी। तापमान बढ़ोतरी में हानिकारक गैसों की भूमिका भी कुछ कम नहीं है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड व जलवाष्प जैसी गैसों के कारण ओजोन परत में छिद्र व ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। इससे खेतीवाड़ी पर प्रतिकूल असर के साथ पर्यावरण के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी हो गई हो रही है।

आज समय की मांग है कि ग्रामीण व किसान कृषि क्षेत्र में पर्यावरण की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने, पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने, कीटनाशकों-खरपतवारनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम संतुलित प्रयोग करने पर अमल करें। अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक कृषि को अपनाने की दिशा में आगे आएं तथा मोटे अनाजों की खेती की ओर उन्मुख होकर पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करें। ऐसे प्रयासों से पर्यावरण और स्वास्थ्य रक्षा के साथ खेतीवाड़ी को पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है। प्रकृति के साथ संतुलन बिठाकर खेती से ही पर्यावरण सुधरेगा और खेती भी फायदे का सौदा बन सकेगी। इससे मानव, पशु पक्षी, पृथ्वी सभी का भला होगा।

मृत पशुओं के शरीर का उचित प्रबंधन

» डॉ. नीलम टांडिया
» डॉ.अनुराधा नेमा
» डॉ. धर्मेंद्र कुमार
» डॉ. पवन रघुवंशी
» डॉ. प्रिया सिंह
कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी, रीवा (म.प्र.)

भारतीय कृषि प्रणाली में पशु पालन का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे हमें दूध, अंडा, मांस, ऊन आदि आवश्यक उत्पाद मिलते हैं। पशु पालन में पशु एक जीव मात्र है इसलिये पशु में सामान्य या कभी असामान्य मृत्यु का होना आम बात है। मृत पशुओं एवं इनसे पनपने वाले रोग के नियंत्रण के लिए पशु के मृत शरीर का उचित निपटान बहुत ही आवश्यक है।

भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मृत शरीर के निपटान की विधियां पारंपरिक तरीके की है, जैसे कि मृत शरीर को जलाना, दफनाना, प्रतिपादन, भस्मीकरण और खाद बनाना आदि। इन सब विधियों के बावजूद भी आज गांव शहरों में लोग मृत पशु शरीर को अमानवीय तरीकों से इसका निपटान करते हैं जैसे मृत शरीर को घसीट कर सड़कों, खेतों और नदियों के किनारे सड़ने के लिए फेंक देते हैं और बहती नदियों में बहा देते हैं, जो पर्यावरण को दूषित और आसपास के जीव जंतुओं के बीमारियों का कारण बनते हैं ।

यह घटना तब ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब यह बीमारियां अत्यधिक संक्रामक हो जाती हैं ।

मृत पशुओं के शव निपटारण की प्रमुख विधियां:

1. शवाधान

2. भस्मीकरण

शव निपटारण के लिए यह दो विधियां उत्तम है ।

शवाधान: यह सबसे आम तरीका है और सुरक्षित भी है। इसमें गड्ढे की गहराई इलाके के स्तर से कम से कम 2 मीटर नीचे और भू जलस्तर से ऊपर होना चाहिये। गड्ढे का आकार मृत पशु के शरीर पर निर्भर करता है। इस विधि में गडडा इतना गहरा होना चाहिए जिससे मृत पशु के शरीर का सबसे उपरी हिस्सा भूस्तर से कम से कम 1.5 मीटर नीचे होना चाहिए ।

इस विधि में ध्यान रखने योग्य बातें: शव के अलावा मृत जानवर द्वारा बचा हुआ चारा, मल मूत्र और शव के नीचे की 5 सेंटीमीटर मिटटी के फर्श को भी शव के साथ दफनाया जाना चाहिए। शव के निस्तारण का स्थान जलभराब क्षेत्र में नहीं होना चाहिये, और न ही आसपास पेय जल स्त्रोत होना चाहिए। साथ ही शव के निपटारण का स्थान गाँव शहर या जल स्त्रोत से कम से कम 250-300 मीटर दूर होना चाहिए।

अगर पशु की मृत्यु सामान्य हुई है और हम पशु की त्वचा निकलना चाहते हैं तो त्वचा निकलने के बाद पशु को फिनोल से भिगो देना चाहिए। फिर शव को चारों तरफ से चूने से ढककर और मिटटी से भर दिया जाता है और कुछ ठोस वस्तुओं को शीर्ष पर रख दिया जाता है, जिससे मांसाहारी पशु शव को बाहर न निकाल पाए।

एंथ्रेक्स के मामले में शव को निपटान से पहले पशु चिकित्सक से परामर्श ले जिसमे पशु के सभी प्राकृतिक छिद्रों (नाक, कान, मुहं, मल और मूत्र द्वार) में रुई (कपास) को 5 प्रतिशत क्रिसोल में भिगोकर शव के प्राकृतिक छिद्रों को बंद कर देना चहिये तथा किसी कपडे या थैले को भी 5प्रतिशत क्रिसोल में भिगोकर शव को चरों तरफ से ढक कर दफनाना चाहिए।

इस बीच ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पशु के शव का निपटारण करते समय अपने मुहं पर मास्क व हाथ पर दस्ताने जरूर पहने और शव का निपटारण करने के बाद पूरे शरीर को अच्छे से स्वच्छ करें।

भस्मीकरण या जलाने की प्रक्रिया: इस विधि से मृत पशु के शव का सबसे प्रभावी ढंग से निपटारण होता है। इसके लिए भस्मीकरण उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसका तापमान 600-800 डिग्री सेल्सिअस होता है।

यह विधि उन मृत पशुओं के लिए काफी उपयुक्त है जो गर्मी प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों जैसे बेसिलस एंथ्रेक्स के जीवाणुओं

के कारण मर जाते हैं। अगर आसपास के क्षेत्र में भस्मीकरण तकनीक की व्यवस्था हो तो पशु चिकित्सक के परामर्श से संक्रामक रोग से मरने वाले पशु का निपटारण इस विधि से ही करें । यदि इस तकनीक की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मृत जानवरों और उससे जुडी अन्य सामग्रियों को एक गड्ढे में रखकर जलाया जा सकता है ।

गड्ढे की गहरे 0.5 मीटर हो और इसे पहले लकड़ी से भर दिया जाता है । जिसमे क्रास आयरन बार की मदद से हवा की जगह बनायी जाती है । फिर शव को इस पर रख कर मिटटी के तेल की मदद से प्रज्वलित किया जाता है । पूरी लाश के जलने के बाद खाई को मिटटी से भर दिया जाता है । याद रखे कि यह प्रक्रिया गाँव क्षेत्र से 250-300 मीटर या इससे ज्यादा दूरी पर हो। इस प्रकार मृत पशुओं का शवाधान एवम भस्मीकरण विधि से उचित निपटान कर इनसे पनपने वाले रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है।

दुनिया में 300 करोड़ लोग पौष्टिक खाने से वंचित

विश्वभर में तीन सौ करोड़ (तीन हजार मिलियन) लोग पौष्टिक खाने का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसे यदि फीसदी में आंके तो यह 42 प्रतिशत बैठता है। विश्व में पौष्टिक खाना वहन नहीं कर पाने वालों में अकेले भारत से 97 करोड़ (970 मिलियन) से ज्यादा लोग हैं। भारत की कुल आबादी का 70.5 फीसदी लोग पौष्टिक खाने पर खर्च करने की स्थिति में नहीं होते। ध्यान रहे कि वैश्विक स्तर पर 2017 से 2020 के मध्य पौष्टिक खाने के खर्च में औसतन 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। जबकि नि न मध्य आय वाले देशों में 2017 से 2020 के बीच पौष्टिक खाने के औसत खर्च में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं यदि भारत में पौष्टिक खाने के औसत खर्च को देखा जाए तो इसमें 5.2 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

यह बात दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट (एसओई इन फिगर्स 2023) में कही गई है। यहां ध्यान देने की बात है कि 2020 के बीच में विश्वभर के हर कोने में वैश्विक उपभोक्ता खाद्य मूल्यों में तेज वृद्धि देखी गई थी। इसी वृद्धि ने वैश्विक स्तर पर पौष्टिक खाने के औसत मूल्य में वृद्धि कराई।

2020 में विश्वभर में लगभग 3.1 बिलियन (110 करोड़) लोग पौष्टिक भोजन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे। यह आंकड़े 2019 की तुलना में 11.2 करोड़ अधिक है। इस मतलब है कि पौष्टिक खाने की महंगाई अधिक होने से लोग इससे दूर हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा तय किए गए मातृत्व, शिशु और छोटे बच्चों के पोषण से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर भारत अग्रसर है। बाकि बचे लक्ष्यों में भारत की स्थिति या तो खराब हो रही है या उसमें किसी प्रकार की प्रगति नहीं दिख रही है। मोटेतौर पर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर भारत सहित ज्यादातर देश मोटापा, खून की कमी, मधुमेह और सोडियम सेवन जैसी समस्याओं से पार पाने के लिए पूरी शिद्दत से जूझ रहे हैं।

किसानों को तालाब की गहराई कुछ स्थितियों को छोड़कर 3 मीटर ही रखना होग

खेत में तालाब बनाने मप्र सरकार दे रही 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने एवं किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई के संसाधनों, स्त्रोत के निर्माण, सिंचाई यंत्र आदि पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक है जिनमें तालाब निर्माण भी एक है। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में पहले से चल रही बलराम ताल योजना को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल कर लिया है। सरकार ने पिछले वर्ष 2022 में योजना के तहत कुछ नए संशोधन कर योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है। कृषि विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य जारी कर दिए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

तालाब बनाने के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा

इस योजना में सामान्य कृषकों को अपने खेतों में बलराम ताल निर्माण के लिए स्वीकृत लागत की प्रावधानित अनुदान 40 प्रतिशत अधिकतम 80,000 रुपए के अतिरिक्त लगने वाली राशि का व्यय स्वयं वहन करना होगा। इसी प्रकार लघु सीमान्त कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 80,000 रुपए के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 1,00,000 रुपए के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा।

बनवाना होगा इस तरह का तालाब

जल संग्रहण के लिए किसानों को खेत का निचला हिस्सा सबसे उपयुक्त होता है। वैसे तो तालाब निर्माण के लिए कई आदर्श मॉडल उपलब्ध है। परंतु यह ताल किसानों की निजी भूमि में बनाना है इसलिए तालाब की लम्बाई, चौड़ाई कृषक के पास भूमि उपलब्धता पर निर्भर करती है। पर किसानों को तालाब की गहराई कुछ स्थितियों को छोड़कर 3 मीटर ही रखना होगा।

योजना में क्या संशोधन किया गया है? वर्ष 2022 में मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा योजना में कुछ संशोधन कर सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है। योजना के तहत राज्य के वे सभी किसान जिनके खेतों में पहले से ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन यंत्र स्थापित है अथवा वे किसान जो बलराम तालाब निर्माण के साथ या निर्माण के बाद माइक्रो इरिगेशन (ड्रिप या स्प्रिंकलर) स्थापित करेंगे उन किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

संकर बाजरा नेपियर घासः एक ही खेत में वर्ष भर हरा चारा उत्पादन मॉडल

संकर बाजरा नेपियर घासः एक ही खेत में साल भर हरा चारा उत्पादन मॉडल

शिवपुरी। खेमराज गौर्य

शिवपुरी जिले में आत्मा-जिला प्रशासन-कृषि विज्ञान केन्द्र-पशुपालन विभाग की पहल से नवाचार घटक में संकर बाजरा नेपियर घास के साथ मौसमी हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता के मॉडल को कृषि विज्ञान केन्द्र पर तैयार कराया गया। जिले के किसानों के अलावा अन्य जिलों के किसान भी केंद्र से रोपण सामग्री ले जाकर स्थापित कर रहे हैं।

कब स्थापित करें: आगामी वर्षा (जुलाई-अगस्त) के मौसम में रोपण करें। इससे पूर्व जिसे खेत में लगाना चाहते हैं, वहां खेत की तैयारी अभी से करें। इसे खेत की मेड़ों पर भी लगाया जा सकता है।

कैसे लगाएं: सामान्यत: चारा फसलों को स्थान कम दिया जाता है। लेकिन इस मॉडल में भूमि के कुशल उपयोग करते हुए 3-3 मीटर की दूरी पर कतारों में संकर बाजरा नेपियर घास की रूट स्लिप्स को 45 डिग्री एंगल पर एक तिहाई भाग जमीन के अंदर दबाते हुए 0.5 से 1 मीटर पौधों में अंतर रखते हुए एकल या दो लाइनों में रोपण करना चाहिए।

तकनीक के लाभ: कतारों में तीन मीटर अंतर से लगाए जाने पर अंतर्वर्ती स्थानों में आसानी से यांत्रिक तरीके से खेती की तैयारी के लिए ट्रैक्टर चलाया जा सकता है तथा कतारों के बीच के स्थानों में मौसमी हरे चारे खरीफ में लोबिया/ग्वार तथा रबी में बरसीम/लूसर्न/जई लगाया जाता है। इससे कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से परिपूर्ण हरे चारों का संयोजनयुक्त उत्पादन पशुधन के लिए उत्पादन प्राप्त होता रहता है जो पशुधन के दूध उत्पादन बढ़ाने में लाभकारी है। इससे दाने की निर्भरता भी कम होने से डेयरी खर्च के व्यय में कमी भी लाई जा सकती है।

कितना उत्पादन: एक ही खेत में वर्ष भर हरा चारा उत्पादन मॉडल से 200 से 250 टन/हेक्टेयर/वर्ष हरा चारा प्राप्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तकनीक से वर्ष भर पशुधन के लिए हरे चारे की प्राप्ति होती रहती है। जिससे स्टॉल फीडिंग में बहुत मदद होती है।

संकर बाजरा नेपियर घास के साथ मौसमी हरे चारे लगाकर पशुपालक बंधु डेयरी व्यवसाय को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं तथा व्यय को भी कम करते हुए पौष्टिक हरा चारा वर्ष भर एक ही खेत से निरंतर मिलता भी रहता है।

डॉ. पुनीत कुमार राठौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषिविज्ञान केंद्र, शिवपुरी

यह तकनीक भा.कृ.अनु.प.भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी की है जिसे राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय से नवाचार घटक में प्रसारित करता आ रहा है। पशुधन रखने वाले/प्राकृतिक खेती अपनाए जाने वाले कृषकों से यह मॉडल लगाए जाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं।

डॉ. एमके भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान) एवं प्रभारी प्राकृतिक खेती कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी

सराहा एवं दिया मार्गदर्शनः डॉ. अमरेश चन्द्रा, निदेशक, डॉ. एके रॉय परियोजना प्रभारी पीसीएफसी एवं डॉ. विजय यादव विभागाध्यक्ष, बीज तकनीकी संभाग एवं वर्तमान में परियोजना प्रभारी पीसीएफसी, भा.कृ.अनु.प.-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के दल ने केन्द्र पर भ्रमण कर संस्थान की तकनीक के प्रसारित करने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए और भी अधिक कुशलता के लिए केन्द्र के वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन भी दिया, जिससे चारा तकनीकियों का अधिक से अधिक प्रसार कृषकों/पशुपालकों तक हो सके।

प्राप्ति स्थान: गुणवत्तायुक्त रूट स्लिप कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी या आईजीएफआरआई झांसी से प्राप्त कर सकते हैं।

मई-जून में कटाई छटाई की दी समसामयिक जानकारी

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कैसे लें अमरूद के बाग में ज्यादा उत्पादन

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञानं केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. बीएस किरार एवं वैज्ञानिक डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह. और जयपाल छिगारहा के द्वारा के बताया गया कि माह मई-से जून के प्रथम सप्ताह मे अमरूद के सघन बागवानी की कटाई छटाई अति आवश्यक है। अमरूद के सघन बागवानी की दूरी 6-3 मीटर होती है। आमतौर पर अमरूद के बाग लगाने की सामान्य दूरी 6-6 मीटर होती है। सघन बागवानी में कुल 555 पौधे और सामान्य पौधरोपण विधि से 277 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाये जाते हैं। सघन बागवानी के लिए पौधों का आकार छोटा रखने के लिए समय-समय पर कटाई छटाई की आवश्यकता पड़ती है, ताकि पौधे से अधिक से अधिक फल प्राप्त किया जा सके। यदि पौधो में फूल एवं फल आ रहे हैं तो 10प्रतिशत अर्थात 10 ग्राम प्रति लीटर की दर से यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे वर्षा ऋतु मे फल न लगने पाए और जब शरद ऋतु मे फल आयेगा वह गुणवत्तायुक्त एवं स्वादिष्ट होगा। अमरुद के दो कदार के बीच में अदरक, हल्दी एवं सूरन लगाकर आय को बढ़ाया जा सकता है। अमरूद के पौधों की कटाई छटाई मुख्य रूप से माह मई से जून के प्रथम सप्ताह तक करते हैं और इस बीच सिंचाई बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। पौधे के आर्तरिक भाग वाली छोटी शाखाएं सघन एवं सशक्त ढांचे का निर्माण करती है।

शाखाओं की कटाई वर्ष में दो बार ही करें

कटाई छटाई द्वारा तैयार किए गए पौधे का व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 2.5 मीटर सीमित रखते हैं। प्रत्येक वर्ष कटाई छटाई की जाती है। आमतौर पर अमरूद के पौधो की शाखाएं 3 से 4 माह की अवधि में परिपक्व हो जाती हैं। इसके लंबाई के आधे भाग (50प्रतिशत) तक काट दिया जाता है, ताकि कटे हुए स्थान के नीचे से नई शाखाए निकल सकें। यह कार्य अपेक्षित कैनोपी तथा सशक्त वृक्ष संरचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अमरुद की शाखाओं की कटाई छटाई वर्ष में दो बार की जाती है। दूसरी कटाई छटाई माह जनवरी में की जाती है। इसके पश्चात बाद में जो नए प्ररोह निकलते हैं उसी पर फूल आने के पश्चात फल लगते हैं। अतः अमरूद के सघन बागवानी से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्ष में दो बार माह मई से जून के प्रथम सप्ताह एवं माह जनवरी में कटाई छटाई किया जाना चाहिए। औसतन अमरूद के सघन बागवानी से 250-300 क्विंटल एवं सामान्य बागवानी से 180 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है।

शरीर में पानी की कमी से बचाने पशु को ग्लूकोज की बोतल ड्रिप चढ़वाएं

पशुओं को लू से बचाने ठंडे पानी से नहलाएं और लगाएं पंखा-कूलर

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत गर्म जलवायु वाला देश है, लेकिन राजस्थान में विशेषकर गर्मी मौसम बहुत ही कष्ट और पीड़ादायक होता है। अप्रैल में धूल भरी आंधियां, सांय-सांय की आवाज करती गर्म लू की लपटें इस मौसम की खास विशेषता है। इससे सजीव और मूक पशु भी झुलसने से नहीं बचते यहां की गर्मी की पीड़ा पशुओं को ही अधिक सहन करनी पड़ती है। मौसम के प्रभाव का पशुओं की दिनचर्या से सीधा संबंध है। मौसम की विभिन्नता, इसके बदलाव की स्थिति में पशु के लिए विशेष प्रबंध करने के प्रयासों की आवश्यकता रहती है। हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार मौसम में काफी विविधताएं हैं। वहीं देश के पश्चिम भाग में गर्मी काफी तेज पड़ती है। जरा सी लापरवाही से किसानों को पशुधन की क्षति हो सकती है।

अधिक गर्म समय में पशु के शारीरिक तंत्र में व्यवधान आ जाता है, जिसके कारण गर्मी पशु के शरीर में इकट्ठा हो जाती है तथा सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वह बाहर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से पशु को तेज बुखार आ जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। यही रोग पशु में लू लग जाना कहलाता है। यह रोग अधिक गर्म मौसम जब वातावरण में नमी और ठंडक की कमी आ जाती है तथा तेज गर्म हवाएं चलती हैं, पशु आवास में स्वच्छ वायु नहीं आने के कारण होता है। कम स्थान में अधिक पशु रखने तथा अधिक मेहनत करने से उत्पन्न होने वाली गर्मी से भी यह रोग होता है। गर्मी के मौसम में पशु को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिलाना मुख्य कारण माना जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में तेज लू व सूखी गर्मी पड़ने के कारण वहां पशुओं की ज्यादा हानि होती है।

लू के लक्षण

पशु को लू लगने पर 106 से 108 डिग्री फेरनहाइट तेज बुखार होता है सुस्त होकर खाना-पीना छोड़ देता है, मुंह से जीभ बाहर निकलती है तथा सही तरह से सांस लेने में कठिनाई होती है तथा मुंह के आसपास झाग आ जाता है। लू लगने पर आंख व नाक लाल हो जाती है। प्रायः पशु की नाक से खून आना प्रारंभ हो जाता है जिसे हम नक्सीर आने पर पशु के हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और श्वास कमजोर पड़ जाती है जिससे पशु चक्कर खाकर गिर जाता है तथा बेहोशी की हालत में ही मर जाता है।

बरतनी चाहिए सावधानी

इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पशु आवास में स्वच्छ वायु जाने एवं दूषित वायु बाहर निकलने के लिए रोशनदान होना चाहिए। तथा गर्म दिनों में पशु को दिन में नहलाना चाहिए खासतौर पर भैंसों को ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। पशु को ठंडा पानी पर्याप्त पिलाना चाहिए। संकर नस्ल के पशु जिनको अधिक गर्मी सहन नहीं होती है उनके आवास में पंखे या कूलर लगाना चाहिए। पशुओं को इस रोग से बचाने में उसके आवास के पास लगे पेड़-पौधे बहुत सहायक होते हैं। लू लगने पर पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसकी पूर्ति के लिए पशु को ग्लूकोज की बोतल ड्रिप चढ़वानी चाहिए तथा बुखार को कम करने व नक्सीर के उपचार की विस्तार से जानकारी लेने व चिकित्सा के लिए तुरन्त पशु चिकित्सक से सलाह लें।

पानी व्यवस्था

इस मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास अधिक। पशुपालको पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम तीन बार पानी पिलाना चाहिए। जिससे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक एवं आटा मिलाकर पानी पिलाना चाहिए।

पशु आहार गर्मी के मौसम में दुग्ध उत्पादन एवं पशु की शारीरिक क्षमता बनाए रखने की दृष्टि से पशु आहार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। गर्मी के मौसम में पशुओं को हरे चारे की अधिक मात्रा उपलब्ध कराना चाहिए। इसके दो लाभ हैं, एक पशु अधिक चाव से स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चारा खाकर अपनी उदरपूर्ति करता है, तथा दूसरा हरे चारे में 70-90 प्रतिशत तक पानी की मात्रा होती है, जो समय-समय पर जल की पूर्ति करता है। प्रायः गर्मी में मौसम में हरे चारे का अभाव रहता है। इसलिए पशुपालक को चाहिए कि गर्मी के मौसम में हरे चारे के लिए मार्च, अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काऊपी, बरबटी आदि की बुवाई कर दें, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। ऐसे पशुपालन जिनके पास सिंचित भूमि नहीं है, उन्हें समय से पहले हरी घास काटकर एवं सुखाकर तैयार कर लेना चाहिए। यह घास प्रोटीन युक्त, हल्की व पौष्टिक होती है।

भैंस की बेहतरीन नस्लें, किसानों को करा सकती है बंपर कमाई

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर खेती के साथ- साथ किसान बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स बेचकर देश में लाखों किसानों के घर का खर्च चल रहा है। कोई किसान गोपालन करना पसंद करता है, तो कोई भैंस पालन। हालांकि, भैंस का दूध गाय के दूध के मुकाबले महंगा बिकता है। अगर किसान भाई अच्छी नस्ल की भैंस का पालन करते हैं, तो दूध बेचकर बंपर कमाई कर सकते हैं। तो आज हम भैंस की कुछ बेहतरीन नस्लों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका पालन करने से दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।

मुर्राह भैंस- मुर्राह भैंस पूरे भारत में फेमस है। यह अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। इस नस्ल की भैंस रोज 20 लीटर तक दूध दे सकती है। मर्राह नस्ल की भैंस का रंग बिल्कुल काला होता है। इसका सर छोटा होता है। वहीं, इसका सिंग अंगुठी की तरह गोल होता है। यह सबसे महंगी नस्ल की भैंस है। इसका पालन हरियाणा और पंजाब में अधिक किया जाता है। मर्राह भैंस को हरियाणा में 'काला सोना' भी कहा जाता है। इसके दूध में वसा अधिक पाया जाता है। यह भैंस गर्म और ठंडे किसी भी प्रकार की जलवायु में असानी से रह सकती है। इस नस्ल की भैंस की कीमत 80 हजार से एक लाख के बीच होती है।

भदावरी नस्ल की भैंस

भदावरी नस्ल की भैंस अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिला, इटावा जिला और जालौन जिला है। इन जिलों में किसान भदावरी नस्ल की भैंस को अधिक पालते हैं। इसके दूध में 8 प्रतिशत वासा पाई जाती है। भदावरी नस्ल की भैंस का वजन 300 से 400 किलो तक होता है। यह अन्य नस्ल की भैंसों के मुकाबले कम चारा खाती है। इसलिए इसके आहार के ऊपर पशुपालक को कम खर्च करने पड़ते हैं। यह रोज 10 से 12 लीटर दूध आसानी से दे सकती है। इस नस्ल की भैंस की कीमत 70 से 80 हजार रुपए है।

सुर्ती भैंस

डेयरी बिजनेस से जुड़े लोग सुर्ती नस्ल के भैंस का पालन करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यह दूध बहुत अधिक देती है। यह भैंस महीने में 600 लीटर तक दूध देने सकती है। इसके दूध में वासा की मात्रा 8 से 12 प्रतिशत होती है। जाफराबादी भैंस- इस नस्ल की भैंस का वजन बहुत अधिक होता है। इसका मूल स्थान गुजरात के गिर के जंगल हैं। लेकिन अब इसका पालन कच्छ व जामनगर भी किया जा रहा है। इसका सिर और गर्दन का आकार भारी होता है। जबकि इसका माथा काफी चौड़ा होता। यह भैंस महीने में 1000 लीटर तक दूध दे सकती है।

खेती का खास तरीका अपने से किसानों को धान के मुकाबले अच्छी कमाई होगी

जून में इन सब्जियों की खेती किसानों के लिए हो सकती है फायदेमंद

भोपाल। जागत गांव हमार

इस बार जून के पहले हफ्ते में मानसून दस्तक दे रहा है। इसके साथ ही बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और किसान धान की खेती की तैयार में लग जाएंगे। ऐसे लोगों को लगता है कि मानसून के आगमन के बाद केवल धान की ही खेती की जा सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जून के महीने में हरी सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं। इससे आपकी धान के मुकाबले अच्छी कमाई होगी। बस इसके लिए खेती का खास तरीका अपनाना होगा।

पालक- किसान भाई जून के महीने में पालक की बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए खेत की 3 से 4 बार जुताई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। फिर, खाद के रूप में खेत में गाय का गोबर डालें और पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लें। इसके बाद क्यारी बनाकर आप पालक की बोवनी कर सकते हैं। एक महीने के बाद पालक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी कटाई कर आप मार्केट में बेच सकते हैं। मार्केट में पालक का रेट हमेशा 20 से 30 रुपए किलो रहता है। इस तरह आप पालक की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं।

भिंडी और खीरा जून महीने में भिंडी और खीरे की खेती करना भी बेहतर रहेगा। अगर किसान भाई अभी भिंडी और खीरे की बोवनी करते हैं, अगस्त से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। आप अक्टूबर महीने तक बागान से खीरा और भिंडी तोड़ सकते हैं। बरसात के मौसम में भिंडी जहां 60 से 80 रुपए किलो बिकती है, वहीं खीरा भी 40 रुपए किलो हो जाता है। इस तरह किसान भाई भिंडी और खीरा बेच कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

करेला, लौकी, तोरइ

इसी तरह जून के महीने में करेला, लौकी और तोरई की बुवाई करना भी किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा। बरसात के मौसम में इन फसलों का ज्यादा उत्पादन मिलता है। खास बात ये है कि ये तीनों फसलें 40 दिन में तैयार हो जाती है। इसका मतलब आप 40 के दिन बाद सब्जी की तुड़ाई कर सकते हैं। इन सब्जियों को बेचकर किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं।

बैगन, मिर्च, टमाटर

अगर किसान भाई चाहें तो जून में पॉली हाउस के अंदर बैगन, मिर्च और टमाटर की भी खेती शुरू कर सकते हैं। इससे किसानों को अच्छी आमदनी होगी। बरसात में टमाटर का रेट बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे में किसान भाई टमाटर बेच कर फायदा कमा सकते हैं।

ककोड़ा के फलों का सेवन करने से मधुमेह रोगी के शर्करा नियंत्रण में भी बहुत उपयोगी

ककोड़ा-परोड़ा की उन्नत खेती, स्वादिष्ट और पौष्टिक के साथ किसानों के लिए लाभदायक

डॉ. रमेश अमूले,
आरएल राऊत
डॉ.एसआर धुवारे
कृषि विज्ञान केंद्र, बड़ागांव,
बालाघाट, जवाहरलाल नेहरू
कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

ककोड़ा (खेख्सा) एक बहुवर्षीय कद्दूवर्गीय भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। ककोड़ा को काटवल व परोड़ा, खेख्सी के नाम से भी जाना जाता हैं। विशेषकर जंगली क्षेत्रों में स्वयं उगते हुए देखे जा सकते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों के आस-पास के लोग इसकी सब्जी के रूप में बहुतायत से उपयोग करते हैं। ककोड़ा के बीज को एक बार लगाने के बाद इसके मादा पौधे से लगभग 8-10 वर्षों तक फल प्राप्त होते रहते हैं। यह स्वाद में अधिक स्वादिष्ट और पोषक तत्व से भरपूर सब्जी है, जिस वजह से इसका बाजार भाव काफी अच्छा होता है। किसानों के लिए यह एक अच्छी कमाई का साधन भी है, जिस वजह से ककोड़ा की खेती मुनाफे की खेती भी कही जाती है। फलों का उपयोग अचार बनाने के लिए भी किया जाता है। यह कफ, खांसी, अरूचि, वात, पित्तनाशक और हृदय में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है। इसकी जड़ों का उपयोग बवासीर में रक्त बहाव रोकने के लिए, पेशाब की शिकायत व बुखार होने पर बहुत लाभकारी होता है। ककोड़ा के फलों का सेवन करने से मधुमेह रोगी के शर्करा नियंत्रण में भी बहुत उपयोगी है।

जलवायु

ककोड़ा गर्म और कम सर्द मौसम की फसल है। इस सब्जी की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। इस फसल को बेहतर विकास और उपज के लिए अच्छी धूप की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त है।

खेख्सा के लिए भूमि

ककोड़ा की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। परन्तु इसकी खेती रेतीली भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो, अच्छी रहती है। इसके साथ ही मृदा का पी एच। मान 6-7 के बीच होना चाहिए। ककोड़ा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील होती है।

बोवनी का समय

ककोड़ा के बीजों की बोवनी का समय जून-जुलाई है। बीज के साथ-साथ ककोड़ा का प्रवर्धन उसके वानस्पतिक अंगों से भी किया जाता है। बीजों के द्वारा प्रवर्धन से 1ः1 के अनुपात में नर व मादा पौधे मिलते हैं। इसलिए ककोड़ा की फसल के लिए बीजों का प्रयोग नहीं करें। ककोड़ा की खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करने प्रवर्धन वानस्पतिक भाग अर्थात जड़ के कंद द्वारा करना चाहिए।

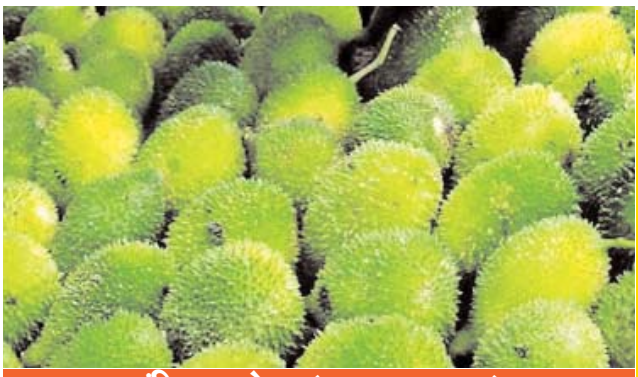

इंदिरा ककोड़ा 1 (आरएमएफ- 37)

एक नई व्यावसायिक किस्म है, जिसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। इस किस्म की खेती उत्तर प्रदेश, ओड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में की जा सकती है। यह बेहतर किस्म सभी प्रमुख कीटों और कीड़ों के लिए प्रतिरोधी है। यह तुड़ाई के लिए 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। यदि इसके बीजों को ट्यूबर्स में उगाते हैं तो यह 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म की औसतन उपज पहले साल 4 क्विंटल/एकड़ है, दूसरे साल 6 क्विंटल/एकड़ और तीसरे साल 8 क्विंटल/एकड़ होती है।

बीज की मात्रा| सही बीज जिसमें कम से कम 70-80 प्रतिशत तक अंकुरण की क्षमता हो। ऐसे बीज की 8-10 किग्रा। प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कंद से रोपण के लिये 10000 कंद प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।

बिजाई और अंतरण| तैयार बेड में 2 सेंटीमीटर की गहराई में 2 से 3 बीज बोएं, मेड़ से मेड़ का फासला लगभग 1 मीटर या पौधे से पौधे का फासला लगभग 1 मीटर होना चाहिए।

बोवनी की विधि| ककोड़ा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत में पौधों की संख्या पर्याप्त होना आवश्यक है। इस फसल की बोवनी अच्छी प्रकार तैयार खेत में क्यारी बनाकर अथवा गड्ढों में किया जाता है। गड्ढे की आपस में दूरी 1-1 मीटर रखनी चाहिए। प्रत्येक गड्ढे में 2-3 बीज की बोवनी करते हैं जिसमें बीच वाले गड्ढे में नर पौधा रखते हैं तथा बाकी गड्ढों में मादा पौधों को रखते हैं। यह भी ध्यान रखें कि एक गड्ढे में एक ही पौधा रखा जाता है।

खाद व उर्वरक| ककोड़ा की खेती का लाभ लेने 200 से 250 क्विंटल प्रति हे. अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में डालकर मिट्टी में मिला दें। इसके अलावा 65 किलो यूरिया, 375 किग्रा एसएसपी तथा 67 किग्रा। एमओपी प्रति हेक्टेयर दें।

फसल प्रबंधन

इस पर बहुत कम कीट व व्याधियों का प्रकोप होता है। परन्तु फल मक्खी ककोड़ा के फलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड या इन्डोक्साकार्ब 14.5 एससी की 1.5-2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर फसल की सुरक्षा की जा सकती है।

ककोड़ा के फसल की कटाई

ककोड़ा के फसल की कटाई व्यापारिक उद्देश्य और गुणवत्ता के अनुसार की जाती हैं। सब्जी के रूप में ककोड़ा की पहली कटाई दो से तीन माह पश्चात् की जा सकती हैं। इस दौरान आपको ताजे स्वस्थ और छोटे आकार के ककोड़ा की फसल मिल जाती हैं। इसके आलावा फसल की कटाई एक वर्ष बाद भी की जा सकती है, इस दौरान फसल की गुणवत्ता काफी अच्छी पायी जाती हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले ककोड़ा की मांग बाजारों में काफी अधिक रहती हैं। ककोड़ा का बाजारी भाव गुणवत्ता के हिसाब से 150 रुपए या उससे भी अधिक हो सकता हैं। इस हिसाब से किसान भाई ककोड़ा की एक बार की फसल से अच्छी कमाई करते हैं। यह सब्जी बिजाई के 70 से 80 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह दूसरे वर्ष में 35 से 40 दिनों में तैयार हो जाती हैं।

पौधों को सहारा देना

ककोड़ा से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है। स्टेकिंग करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है तथा गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए बांस या सूखी लकडियों की टहनी आदि से सहारा देना आवश्यक होता है। ककोड़ा एक बहुवर्षीय फसल है इसलिए पौधों को सहारा देने के लिए लोहे के एंगल पर जालीनुमा तार 5-6 फीट ऊंची, 4 फीट गोलाकार संरचना का उपयोग कर सकते हैं जिससे अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं।

सिंचाई, निंदाई-गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण

फसल की बोवनी के तुरन्त बाद खेत में हल्की सिंचाई करें। बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु दो वर्षा के समय में अधिक अन्तर होने पर सिंचाई करें। खेत में आवश्यकता से अधिक पानी को बाहर निकालने के लिए जल निकास की भी व्यवस्था हो क्योंकि अधिक पानी से बीज या कन्द सड़ सकता है। ककोड़ा की फसल में खरपतवार नियंत्रण की अधिक जरूरत नहीं होती है। परन्तु खेत खरपतवार रहित रहे, इसकी फसल में केवल दो से तीन गुड़ाई की जरूरत होती हैं। बेल को सहारा देने के लिए उचित व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है।

बंपर उपज के लिए ऐसे तैयार करें धान की नर्सरी, रोगों से भी मिलेगा छुटकारा

भोपाल। जागत गांव हमार

धान की बोवनी शुरू करने से पहले किसानों को कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे धान की बर्बाद कम होगी और बंपर पैदावार मिलेगी।

किसान धान की नर्सरी तैयार करने के लिए हमेशा प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। इससे पैदावार बढ़ जाती है। कई राज्यों में राज्य सरकारें बंपर सब्सिडी पर प्रमाणित धान के बीज किसानों को दे रही है। इन राज्यों के किसानों को असानी से प्रमाणित बीज मिल जाएंगे। अगर किसान इन प्रमाणित बीजों का शोधन कर बोवनी करते हैं, तो फसल में कई तरह के रोग नहीं लगते हैं। यानी शोधित बीज से तैयार धान की फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती हैं।

बीज का शोधन करने पर महज 20 से 30 रुपए ही खर्च होंगे- खास बात है कि बीजों का शोधन करने की प्रक्रिया महंगी नहीं है। किसान भाई घर पर खुद से ही बीजों का शोधन कर सकते हैं। एक हेक्टेयर में धान के बीज का शोधन करने पर महज 20 से 30 रुपए ही खर्च होंगे। इसके लिए किसान भाइयों को 25 किलो धान के बीज में 75 ग्राम थीरम और 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लीन मिलाकर उसे शोधित कर सकते हैं। इससे इन बीजों से तैयार धान की फसल में रोग नहीं लगेंगे।

ऐसे करें कीटनाशकों का छिड़काव

वहीं, धान की नर्सरी तैयार करते समय कीट- पतंगों का भी खतरा बना रहता है। इसलिए कीटों के प्रकोप से नर्सरी को बचाने के लिए एक हेक्टेयर में 1।25 लीटर क्लोरोसाइपार या 250 एमएल इमिडाक्लोप्रिड को पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इससे कीटों का हमला नहीं होगा। अगर किसान भाई अपनी धान की नर्सरी को खैरा रोग से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें 400 ग्राम जिंक सल्फेट को 1।6 किलो यूरिया के साथ 60 लीटर पानी में मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। इसके बाद नर्सरी में इसका छिड़काव करें। इससे खैरा रोग का खतरा बहुत कम हो जाता है। साथ ही कम समय में ही अच्छी धान की नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके बाद आप पहले से तैयार खेत में धान की बोवनी कर सते हैं।

मोटा अनाज के उत्पादन पर फोकस

रीवा। कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा में 25वीं वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के संचालक विस्तार सेंवाएं डॉ. डीपी शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा के प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. अजय कुमार पांडेय नें कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा रबी-2022-23 की प्रगति प्रतिवेदन एवं खरीफ-2023 में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की कार्य योजना पावर प्वाइंट आनलाईन द्वारा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में कृषि महाविधालय रीवा के अधिष्ठाता डॉ. एसके पयासी ने खरीफ में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयुक्त सुझाव दिया। कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. बीएम मौर्या एवं डॉ. आरपी जोशी ने दलहन व मोटा अनाज की उन्नत तकनीकी पर चर्चा करते हुए इसका व्यापक प्रसार करने पर बल दिया।

उक्त बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कार्यक्रम में आगामी कृषि कार्य योजना से संबंधित विस्तृत चर्चा में कृषि विभाग, उद्यानिकी, मत्स्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, आत्मा, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि उत्पादक संगठन, एनजीओ, आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा मशरूम उत्पादन के प्रशिक्षित युवा, ऐग्री स्टार्टअप के मुबारक खान व प्रगतिशील कृषक बंधु एवं महिला भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से

अधिकारियों ने अपने-अपने विषय में किसानों के हित के लिए सुझाव दिए। कार्यक्रम में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. सीजे सिंह, डॉ. टीके सिंह, डॉ. राजेश तिवारी, डॉ. किंजल्क सिंह, अखिलेश पटेल, स्मिता सिंह, डॉ. केएस बघेल, संदीप शर्मा, एमके मिश्रा, मंजू शुक्ला, डॉ., ब्रजेश सेन, देवान आदिवासी, सत्रुधन वर्मा, गित्री ऋषभ विश्वकर्मा और संजय सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ब्रजेश तिवारी एवं आभार प्रदर्शन डॉ. राजेश सिंह ने किया।

-हॉस्टल और घरों के सामने 100 पिट में लगाए जाएंगे पौधे

अच्छी पहल! बचा भोजन बनेगा पौधों के लिए संजीवनी

भोपाल। जागत गांव हमार

आमतौर पर लोग घर में बचे हुए भोजन को डस्टबिन में डाल देते हैं। यह किसी के काम नहीं आ पाता और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यही भोजन पौधों के लिए संजीवनी भी बन सकता है। वाटर एंड लैंड मैनजमेंट इंस्टीट्यूट (वाल्मी) रोजाना करीब 500 लोगों की थाली में बचे हुए भोजन को पौधों के लिए उपयोगी बना रहा है। इसी के साथ किचन वेस्ट को ट्रीट कर भी पौधों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें केवल फल-सब्जी और जैविक अशिष्ट होता है। वाल्मी के हॉस्टल की क्षमता 240 है। एक समय पर यहां करीब 200 लोग रहते हैं। इसी तरह यहां के अधिकारी-कर्मचारियों के 80 आवास में भी करीब 350 लोग रहते हैं। इनके यहां का बचा हुआ भोजन कचरा गाड़ी में नहीं डाला जाता बल्कि इसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा रहा है।

हर घर के सामने पिट | वाल्मी के अधिकारियों ने बताया कि हॉस्टल कैंपस में 100 से ज्यादा पिट तैयार किए जा रहे हैं। यह एक घन मीटर के हैं। इसी तरह 80 घरों के सामने भी इसी तरह के पिट तैयार किए हैं। इनमें रोजाना बचा हुआ भोजन, चाय पत्ती, सब्जियों के छिलके, फल व अन्य खाद्य सामग्री को डाला जाता है। पिट में डालने के बाद इनसे दुर्गंध न आए इसके लिए मिट्टी की लेयर डाल दी जाती है। यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जा रही है।

मिट्टी की लेयर डाल दी जाएगी

अंत में जब पिट पूरी तरह भर जाएगा तो इस पर गोबर और मिट्टी की लेयर डाल दी जाएगी और पास में ही इसी तरह का नया पिट तैयार किया जाएगा। इसका लाभ यह है कि आसपास के पेड़-पौधों को इससे पोषक तत्व मिलेंगे और इसी के साथ बारिश में इन पिट पर भी पौधरोपण करेंगे। इसकी खासियत यह है कि फिर किसी भी पौधे को अलग से खाद-मिट्टी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

पोषक तत्व मिलेंगे

संस्थान की डायरेक्टर उर्मिला शुक्ला के मुताबिक यह वाल्मी की इजाद की हुई तकनीक है। इससे जैविक अपशिष्ट पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को रिसायकल कर पौधों के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है।

अटल पथ के सेंट्रल वर्ज पर पाम ट्री लगाने का प्रयोग फेल

दो साल में दूसरी बार सूख गए पौधे

भोपाल। स्मार्ट सिटी एरिया में आम, जाम, नीम, पीपल, आंवला, जैसे देसी प्रजातियों के पेड़ काटकर बुलेवर्ड स्ट्रीट यानी अटल पथ पर सवा करोड़ रुपए खर्च कर पाम ट्री लगाने का प्रयोग असफल साबित हुआ है। यहां सेंट्रल वर्ज पर लगे कम से कम 15 पेड़ फिर सूख गए। स्मार्ट सिटी कंपनी ने इन्हें कचरे में फेंक दिया है। करीब एक साल पहले भी यहां के 33 पेड़ सूख गए थे, जिन्हें रिप्लेस किया गया था। दो साल पहले जब यहां पेड़ लगाए जा रहे थे, उसी समय जानकारों ने कहा था कि पाम ट्री लगाना भोपाल की जलवायु के लिहाज से ठीक नहीं है। ये समुद्र किनारे लगाए जाते हैं, क्योंकि यह ग्राउंड वॉटर को सोखता है। एक

साल के भीतर ही यह पेड़ सूख गए, इसके बाद स्मार्ट सिटी कंपनी ने यहां फिर से पाम ट्री लगाए और यह फिर सूखने लगे हैं। लगभग 40 करोड़ से बनी डेढ़ किमी सड़क के सेंट्रल वर्ज पर खूबसूरती बढ़ाने के नाम पर लगे यह पेड़ सूखने के बाद एक बदनुमा दाग नजर आ रहे हैं।

मेंटेनेंस की जिम्मेदारी

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्मार्ट सिटी उपदेश शर्मा ने बताया कि जो भी पाम ट्री रिप्लेस किए जाएंगे, उनके लिए स्मार्ट सिटी को कोई पेमेंट नहीं करना है। इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कॉन्ट्रेक्टर की ही है।

बर्बाद की हरियाली

स्मार्ट सिटी की इस लोकेशन पर 342 एकड़ एरिया में लगभग 6000 पेड़ लगे थे। पूरे क्षेत्र में 2000 से मकानों के आंगन और अन्य खुली जगह पर आम, नीम, पीपल, बढ़, अमरूद समेत अन्य प्रजाति के पेड़ लगे हुए थे। इसमें से लगभग 3000 पेड़ काटे या नष्ट किए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी की पर्यावरण स्वीकृति रिपोर्ट में खास तौर से इस बात का जिक्र है कि इस इलाके में देशज प्रजाति के पेड़ ही लगाए जाने हैं।

'प्रति बूंद अधिक फसल' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न

नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटनमनोज आहूजा, सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने किया। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिभागी, सिंचाई उद्योग, जल प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आहूजा ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकियों को अपनाने और सूक्ष्म सिंचाई कवरेज को बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि इसके द्वारा देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि और विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव डॉ. हिमांशु पाठक ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे कृषि क्षेत्र में जल के उपयोग को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए प्रयास करें।

-शिवपुरी के किसान बोले- मोदी जी प्याज निर्यात की दी जाए अनुमति

मोदी जी! निर्यात की दें अनुमति, पहले टमाटर तो अब प्याज ने निकाले आंसू

शिवपुरी। जागत गांव हमार

शिवपुरी में इस साल प्याज का बंपर उत्पादन हुआ है। बंपर उत्पादन के बीच 200 से 300 ट्रॉली प्रतिदिन शिवपुरी की पिपरसमां मंडी में प्याज आ रही है। इसके विपरीत दूसरे प्रदेशों में प्याज की डिमांड नहीं है, जिसके कारण प्याज के सही रेट किसानों को नहीं मिल पा रहे। किसानों को स्थानीय व्यापारियों ने बताया है कि पहले शिवपुरी की प्याज आगरा, दिल्ली, आगरा, कानपुर और नेपाल तक जाती थी, लेकिन अब इन क्षेत्रों में प्याज की डिमांड नहीं है। इसके अलावा निर्यात पर भी प्रतिबंध है जिसके कारण प्याज के दाम किसानों को सही नहीं मिल पा रहे हैं। शिवपुरी के किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को प्याज का निर्यात प्रारंभ करवाना चाहिए, जिससे कि किसानों को उचित दाम मिल सकें। किसानों ने बताया कि इस समय देश से प्याज निर्यात पर प्रतिबंध है जिसके कारण देश से बाहर प्याज नहीं जा पा रहा है। किसानों का कहना है कि देश की प्याज पाकिस्तान सहित अन्य देशों में जाएगी तो इसके किसानों को सही दाम मिल पाएंगे। जिससे किसानों को कुछ फायदा होगा।

पहले टमाटर ने रुलाया था | शिवपुरी जिले में टमाटर और प्याज का उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन इस बार इन दोनों ही चीजों के दाम काफी नीचे रहे। टमाटर की भी बाहरी प्रदेशों में कोई डिमांड ना होने के कारण मेन सीजन में टमाटर 2 से 3 रुपए किलो बेचा गया था। जिससे स्थानीय किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। अब प्याज भी किसानों के आंसू निकाल रही है, क्योंकि प्याज भी 5 से 8 रुपए किलो तक बिक पा रही है जिसमें उनकी लागत भी नहीं निकल रही है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)